भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4844

23.03.2026 को उत्तर के लिए

कृत्रिम वर्षा परियोजना

4844. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के साथ साझेदारी से संचालित कृत्रिम वर्षा परियोजना के लिए कुल कितनी सार्वजनिक निधि का उपयोग किया गया है और उस समझौते की विशिष्ट वित्तीय शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस परियोजना को प्रदूषण को कम करने में सफल या विफल मानती है; और

(ग) इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट और समयबद्ध रूपरेखा तैयार की गई है और कृत्रिम वर्षा संबंधी यह प्रयोग किस प्रकार दीर्घकालिक कार्यनीति के अनुकूल हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के सहयोग से "दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के शमन हेतु कृत्रिम वर्षा (क्लाऊड सीडिंग) के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं मूल्यांकन" विषय पर एक प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका परीक्षण अक्टूबर, नवंबर 2025 तथा जनवरी 2026 में किया गया था।

जीएनसीटीडी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अनुदान-सहायता के आधार पर इस परियोजना के लिए ₹3,21,46,000/- (वस्तु एवं सेवा कर सहित) की राशि स्वीकृत की गई है। आई आई टी कानपुर को पहली किश्त के रूप में ₹37,93,420/- की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से आई आई टी कानपुर द्वारा ₹37,71,782/- की राशि का उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने यह भी रिपोर्ट दी है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्य-योजना तैयार की गई है। इस योजना में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से धूल, सड़कों एवं खुले क्षेत्रों की धूल, डीजल जनरेटर सेट एवं बैकअप विद्युत से उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, फसल अवशेष जलाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय, हरित क्षेत्र का विकास तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र-विशिष्ट उपाय शामिल हैं।

*****